power now accounts for only 25.69% of the total installed capacity.

(b) As on 31.3.1998. 22.31% of the assessed hydroelectric potential has either been exploited or is under various stages of construction. However, about 78% of the total assessed potential remains to be exploited.

The main reasons for decline of the hydel share are: resources crunch and cash flow problems; emphsis on thermal/ gas based projects due to longer gestation of hydro porjects; land acquisition and rehabilitation problems; law and order problems; dearth of good contractors; Inter-State disputes affecting execution of projects.

(c) A hydro capacity addition of 9,820 MW is anvisaged during the Ninth Plan [1997—2002].

Power Ordinance

62. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the discontent generated by its recent ordinance relating to power;

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the steps taken/contemplated to neutralise it?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) to (c) The Ordinance envisages the setting up of Central and State Electricity Regulatory Commissions. The primary functions of the Electricity Regulatory Commissions is to evolve a retail electricity tariff structure that is considered necessary for enhancing the overall efficiency of the power sector.

विद्युत उत्पादन विकास निधि से ऋण

63. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन में लगे निजी क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक घरानों को विद्युत उत्पादन विकास निधि से ऋण दिये गए थे;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1997 के अन्त में बकाया ऋणों का औद्योगिक घराने-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऋणों के भुगतान के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसंधान और विकास कार्य के लिये विद्युत उत्पादन निधि से कितनी राशि का अनुदान और ऋण उपलब्ध कराया गया?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) विद्युत उत्पादन विकास निधि नामक कोई निधि नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भांडेर विद्युत परियोजना

64. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी से चलाई जा रही भांडेर विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उपरोक्त परियोजना की लागत और वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है तथा सरकार ने इस परियोजना को किन-किन मानदंडों और शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में स्थानीय स्तर पर कितनी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य में मैसर्स भांडेर पावर लिमिटेड द्वारा गठित किए जाने के लिए प्रस्तावित 342 मे०वा० भांडेर संयुक्त साईकिल विद्युत केन्द्र को 197.622 मिलियन अमेरिकी डालर +346.514 करोड़ रु० की अनुमानित समग्र लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जिन शर्तों पर इस परियोजना को तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्रदान की गई है वे अनुबंध में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।